राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

प्रेस विज्ञप्ति

विद्युत उत्पादन की सभी प्रणालियों में जल विद्युत प्रणाली सर्वथा सुरक्षित, स्वच्छ तथा स्वीकार्य है– राज्यपाल

राजभवन नैनीताल दिनांक 21 मई 2011

सैन्ट्रल हिमालयन एन्वायरमेंट एसोसिएशन (चेया) द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में विद्युत उत्पादन की सभी प्रणालियों में जल विद्युत प्रणाली सबसे सुरक्षित, स्वच्छ तथा निरापद/स्वीकार्य है।

''फर्स्ट सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेन्ट समिट 2011'' के उद्घाटन सत्र में **''हाइड्रो प्रोजेक्ट इन माउंटेन रीजन''** विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छोटे बांध, चैक डैम्स, पवन तथा पनचक्कियां प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरूत्थान तथा गाँवों के पारम्परिक कुंए व तालाब को पर्वतीय क्षेत्रों में पुनः शुरू करने के लिए जन–अभियान चलाया जाना आवश्यक है। बड़े बांधों के निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए वन क्षेत्र को पूर्व की स्थिति में लाने के लिए घरेलू नर्सरी व पत्तियों द्वारा जैविक खाद के उत्पादन एंव वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों/योजनाओं के संचालन से स्थानीय लोगों को निरन्तर रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकती है।

इस दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में **चेया** द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सहित, जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत अनुकूलीकरण परिदृश्य, ग्रामीण पर्यटन, सामुदायिक वानिकी जैसे विषयों/मुद्दों को वैचारिक मंथन हेतु सम्मिलित किया गया है।

देश के 11 पर्वतीय राज्यों से आये नीति निर्धारकों, नागरिक समिति के प्रतिनिधियों, विद्वानों, विशेषज्ञों आदि को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा :–**''जल से उत्पादित ऊर्जा प्रणाली, उन पौधों तथा जीवाश्मों को सबसे कम क्षति पहुंचाती है, जो पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रदूषण से उत्सर्जित गैस से उत्पन्न तापमान को नियंत्रित करती है। जल विद्युत जैसे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से जो गुणात्मक लाभ हैं वे थर्मल या न्यूक्लियर ऊर्जा में नहीं है। शक्ति के स्रोत के रूप में स्थापित *न्यक्लियर एनर्जी* आज विश्व भर में जनसाधारण की बहस का विषय बना हुआ है। जापान में हाल ही में हुई आपदा के बाद आज विकसित देश भी अपने न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं।''**

राज्यपाल ने कहा कि सामान्यतः यह माना जाता है कि बड़े बाँध भौतिक, जैविक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ ही स्थानीय जन–समुदाय के जीवन–यापन, संस्कृति आदि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं परन्तु यह भी है कि विकास की प्रत्येक गतिविधि निश्चित ही कुछ विपरीत प्रभाव भी छोड़ती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बांधों आदि परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों/परिवारों के पुनर्वास प्रबंधन व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि योजनाकारों, को विस्थापितों के लिए पहले से ही उनके बेहतर जीवन–यापन हेतु आयवर्धक गतिविधियों का आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए योजना/कार्यक्रम बनाने चाहिए। मौसम में आ रहे अप्रत्याशित परिवर्तन पर राज्यपाल ने कहा कि सभी हिमालयी राज्यों को, हिमालय के अस्तित्व को बचाने के लिए चलाये जा रहे राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत मौसम परिवर्तन के दृष्टिगत संचालित **कार्ययोजना** को अपनाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए दक्षिण एशियाई राज्यों, जो कि हिमालयी पर्यावरण के साझेदार हैं, के मध्य सूचनाओं के साझे आदान–प्रदान की आवश्यकता भी जताई।

उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की दशा के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए नेटवर्क की स्थापना को आवश्यक बताते हुए कहा कि शहरीकरण, पर्यटन, पेयजल सुरक्षा, ऊर्जा, वन प्रबंधन तथा अवस्थापना के प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है अतः इन पर भी वैचारिक मंथन होना चाहिए।

राज्यपाल ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का आदर्श पर्याय बन चुके हैं **''चिपको आंदोलन''** को पुनर्जागृत करने का आह्वाहन किया।

उन्होंने हिमालयी राज्यों में उपलब्ध असीमित प्राकृतिक वन संसाधनों से होने वाले फायदों की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए कहा कि जैव विविधता से भरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विशाल हरित भू–भाग को विश्व के समक्ष ''आकर्षण केंद्र'' के रूप में स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

राज्यपाल ने वन्य जन्तुओं व मानव के बीच बढ़ते टकराव को भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसका भी समाधान आवश्यक है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस शीर्ष बैठक में निश्चित ही गहन विचार मंथन के बाद जो निर्णय लिए जाएंगे उन्हें कियान्वित करने के लिए बनाई गयी कार्ययोजना, हिमालयी पर्यावरण प्रणाली के बेहतर प्रबंधन, के लिए एक दिशा सूचक अभिलेख साबित होगी।

प्रथम सत्र की इस बैठक में सचिव राज्यपाल श्री अशोक, **चेया** संस्था के अध्यक्ष डा0 आर. एस. टोलिया,डा0 आर. के. पचौरी, जी. आई. जेड. के कन्ट्री डायरेक्टर श्री स्टीफन हेलमिन, डा0 एन्ड्रीज शील्ड, पूर्व मुख्य सचिव श्री इन्दु कुमार पाण्डेय, श्री एन. एस. नपल्च्याल, कुलपति कुमायूं वि0 वि0 डा0 अरोरा, राज्यपाल के परिसहाय श्री वी. के. कृष्ण कुमार, जिलाधिकारी नैनीताल सहित अनेक गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे।

————0————

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 05942–235001